(b) Survey work for trebling the line between Virar and Ahmedabad has been taken up. Further consideration of the project will be possible once the survey report becomes available.

(c) This work is not sanctioned so far.

Budget Allocation for Zonal Training Institutes

4006. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether an allocation of Rs. 3 crores was made in 1995-96 non-plan budget of his Ministry for setting-up of some Zonal Training Institutes;

(b) if so, the details thereof and the places where these Institutes are proposed to be set-up; and

(c) the progress, if any, made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Yes, Sir. An amount of Rs. 3.00 crores was sanctioned to the Kendriya Vidyalaya Sangathan for setting-up of Zonal Institutes of Education and Training.

(b) These institutions are proposed to be opened at the following 5 places:—

(i) Gwalior, Madhya Pradesh
(ii) Sirsa, Haryana
(iii) Bolangir, Orissa
(iv) Karad, Maharashtra
(v) Madurai, Tamilandu

(c) The land for the Institutes has been handed over to Kendriya Vidyalaya Sangathan for Gwalior and Sirsa. Land has been earmarked for Bolangir and Karad. No land has been transferred to Kendriya Vidyalaya Sangathan at Madurai and necessary steps have been taken by Kendriya Vidyalaya Sangathan to expedite the same.

तिलहनों की पैदावार

4007. डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: क्या कृषि मंत्री 2 अगस्त, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2071 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को तिलहनों के लिये मिलने वाला मूल्य उनकी पैदावार लागत से भी कम बैठता है और इस कारण वे इनकी कम मात्रा में पैदावार करते हैं; और

(ख) किसानों को तिलहनों का लाभप्रद मूल्य दिलवाने के लिये सरकार की नीति क्या है और सरकार इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठा रही है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं। पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बाजारों में प्रमुख तिलहनों का औसत थोक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक था जिसमें अन्य भिन्नताओं के अलावा तिलहनों की उत्पादन लागत भी शामिल है। इसके अलावा, तिलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, देश में तिलहन उत्पादन में वृद्धि से परिलक्षित होता है जो 1980-81 के 9.37 मिलियन मी० टन से बढ़कर 1995-96 में 22.90 मिलियन मी० टन (अनुमानित) हो गया है।

(ख) तिलहन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष प्रमुख तिलहनों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय सरकार के विभागों के विचार तथा ऐसे दूसरे संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण समझती है, के आधारित होते हैं। बाजार मूल्यों में, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरावट आने की स्थिति में, समर्थन मूल्य संकार्य के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ (नैफेड) केन्द्रीय नोडल एजेंसी है।